PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Navbharat Times, Delhi
Wednesday 7th January 2015, Page: 11
Width: 8.38 cms, Height: 11.64 cms, a4, Ref: pmin.2015-01-07.48.50

दवाओं के रेट पर रहेगी सरकार की नजर

■ सुरेश उपाध्याय, नई दिल्ली

सरकार ने मूल्य नियंत्रण के दायरे में आने वाली दवाओं की कीमत पर नजर रखने के लिए राज्य स्तर पर स्पेशल टीम बनाने का फैसला किया है। ये टीम राज्य सरकारों को बनानी होंगी और नैशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) इनके साथ मिलकर काम करेगी। गौरतलब है कि प्राइस कंट्रोल के दायरे में आने वाली दवाओं की कीमत सरकार ने तय कर दी है, लेकिन इसके बावजूद कई दवा कंपनियां ज्यादा रेट पर दवाएं बेच रही हैं। इसके कारण हाल ही में जनता से अरबों रुपये ज्यादा वसूल लिए गए, जिसमें से केवल नाममात्र की राशि की वसूली हो पाई है। वसूली पर रोक लगाने के लिए कई कंपनियां कोर्ट में चली गई हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनियां मल्टिनैशनल हैं।

कीमतों पर निगरानी रखने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई

ऑर्डर मानते नहीं

2013 में नया ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जारी होने के बाद कई कंपनियां इसे मानने के मूड में नहीं हैं। वह इसे इंडस्ट्री के हितों के खिलाफ बताती हैं। दिलचस्प यह है कि कई एनजीओ और संगठन इसे जनता के खिलाफ बताते हैं। उनका कहना है कि पहले दवाओं की कीमतें लागत के आधार पर तय होती थीं। अब इसे पूरी तरह से बाजार के हवाले कर दिया गया है।

एनपीपीए की बैठक

बहरहाल कीमतों पर नजर रखने के मामले में हाल में ही एनपीपीए ने राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें तय किया गया कि एनपीपीए के साथ ही राज्य भी दवाओं के दाम पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीम बनाएगा।